



वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग पहल

प्रलिस के लिये:

[वित्तीय साक्षरता](#), [वित्तीय समावेशन](#), [गरीबी](#), [असमानता](#), [भारतीय रज़िर्व बैंक](#), [भारतीय प्रतभित और वनियमि बोरड](#), [भारतीय बीमा वनियमिमक और वकिस प्ररधकिरण](#), [पेंशन फंड वनियमिमक और वकिस प्ररधकिरण](#), [अटल पेंशन योजनर](#)

मुख्य परीकषर के लिये :

वित्तीय साक्षरतर करर महत्त्व, भरतर के लिये वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग पहल, इसकी उपलब्धियें और चुनौतियें

वित्तीय साक्षरतर और वित्तीय समावेशन क्यर है?

वित्तीय साक्षरतर:

परचिय:

- **वित्तीय साक्षरतर** वह जागरूकतर, ज्ञरन, दृष्टकिरण, व्यवहर और कौशल है जो वित्तीय उपकरणों को समझने तथर उनकर उपयोग करने हेतु आवश्यक है, तकर सूचति वित्तीय नरिणय लिये जर सकें और व्यक्तगित वित्तीय कल्याण प्ररपूत कयि जर सकें ।
- इसे पढ़ने, वित्तीय पॉडकस्टर सुनने, वित्तीय सामग्री कर अनुसरण करने यर कसिी वित्तीय वशिषज्ज से पररमरश के मरध्यम से वकिसति कयि जर सकतर है ।

मुख्य भरग:

- **बजट बनरनर:** बजट बनरने और बनरए रखने कर तररीकर समझनर ।
- **बचत और नविश:** बचत के महत्त्व तथर नविश की प्रमुख जनकररी ।
- **ऋण प्रबंधन:** यह समझनर कर ऋण कैसे करर करतर है और ऋण कर प्रबंधन कैसे कयि जरतर है ।
- **वित्तीय योजनर:** वित्तीय लक्ष्य नरिधररति करनर और उन्हें प्ररपूत करने के लिये योजनरए बनरनर ।

वित्तीय साक्षरतर की स्थति:

- **ररषटरीय वित्तीय शकिषर केंद्र** के अनुसार, केवल 27% भरतीय वयस्क वित्तीय रूप से साक्षर हैं ।
- वशिष स्तर पर, **एक चौथरई से भी कम** युवर वयस्क अपनी वित्तीय समझ के प्रतरररश्वस्त महसूस करते हैं ।

वित्तीय समावेशन:

परचिय:

- **वित्तीय समावेशन** से तरत्परय वित्तीय उत्पादों और सेवरओं (बचत, ऋण, बीमर, भुगतन, आदर) को सभी व्यक्तियें तथर व्यवसरयों, वशिष रूप से हरशरि पर पड़े एवं नमिन आय वर्ग के लोगों के लिये सुलभ व सस्ती बनरने के प्ररयसों से है ।

वित्तीय समावेशन के प्रमुख घटक:

- **वित्तीय सेवरओं तक पहुँच:** यह सुनशिचति करनर कर **बैंकिंग**, **बीमर** और **ऋण** जैसी वित्तीय सेवरएँ सभी के लिये उपलब्ध हें । इसमें वंचति कषेत्रों में भौतिक बैंकिंग आउटलेट की स्थापनर तथर **डिजिटल वित्तीय सेवरओं** कर प्रररधन शरमलि है ।
- **वहनीयतर:** वित्तीय उत्पादों और सेवरओं की कीमत ऐसी होनी चरहयि कविे समरज के सभी वर्गों के लिये सुलभ हें । उच्च लगत, वशिष रूप से नमिन आय वर्ग के लिये, एक महत्त्वपूर्ण बरधर हो सकती है ।
- **वित्तीय साक्षरतर:** वित्तीय उत्पादों, सेवरओं और प्रबंधन के संबंध में व्यक्तियें को शकिषति करनर आवश्यक है । **वित्तीय साक्षरतर** लोगों को बचत, नविश तथर ऋण प्रबंधन सहति अपने वतित के बररे में सूचति नरिणय लेने में सकषम बनरती है ।
- **उपयोग:** वित्तीय स्थररतर और वकिस प्ररपूत करने के लिये वित्तीय सेवरओं तक पहुँच से परे यह महत्त्वपूर्ण है कविे व्यक्तिसकरयि रूप से वित्तीय सेवरओं कर उपयोग करें । इसमें बैंकिंग सेवरओं से जुड़नर, ऋण कर ज़मिमेदररी से उपयोग करनर और बीमर उत्पादों कर लरभ उठरनर शरमलि है ।

महत्त्व:

- **सशक्तीकरण और स्वतंत्रतर:** वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति बेहरतर वित्तीय नरिणय लेने में अधकि सकषम होते हैं, जसिसे शोषण की संभरवनर कम हो जरती है ।
- **आरथकि वकिस:** वित्तीय समावेशन बचत को बढ़रवर देकर, रोज़गरर सृजन करके और उत्पादकरतर बढ़रकर आरथकि वकिस को बढ़रवर देतर है ।

- असमानता में कमी: वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके, वित्तीय समावेशन [गरीबी](#) और [असमानता](#) को दूर कर सकता है।
- वित्तीय स्थिरता: वित्तीय रूप से साक्षर जनसंख्या अधिक वित्तीय स्थिरता ला सकती है, क्योंकि व्यक्ति आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिये बेहतर रूप से तैयार होते हैं।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

भारत में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के लिये क्या पहल हैं?

RBI की पहल:

■ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (NCFE):

- इसकी स्थापना वर्ष 2013 में [भारतीय रजिस्ट्रार बैंक \(RBI\)](#), [भारतीय प्रतभुति और वनियमि बोरड \(Securities and Exchange Board of India- SEBI\)](#), [भारतीय बीमा वनियामक और विकास प्राधकिरण \(Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI\)](#), [पेंशन फंड वनियामक और विकास प्राधकिरण \(Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA\)](#) के सहयोग से की गई थी।
- यह कार्यशालाओं, सेमिनारों और अभियानों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य बच्चों, युवाओं, महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के सभी वर्गों तक पहुँचना है।
- NCFE ने वर्ष 2016 और 2020 (NCFE रिपोर्ट 2020) के बीच युवाओं में वित्तीय साक्षरता में 17% की वृद्धि दर्ज की है।
- वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति (NCFE) 2020-25 "5 C" दृष्टिकोण को अपनाती है - सामग्री, क्षमता, समुदाय के नेतृत्व वाला मॉडल, संचार और सहयोग, और वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है।
- इस रणनीति का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 500 मिलियन भारतीयों को वित्तीय रूप से सशक्त और जागरूक बनाना है।
- रणनीति का ध्यान सामग्री वकिसति करने, क्षमता निर्माण, समुदाय-आधारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और वभिनिन हतिधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।

■ वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLC):

- RBI ने पूरे भारत में, खास तौर पर ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी इलाकों में, 1,500 से अधिक वित्तीय साक्षरता केंद्र (Financial Literacy Centres- FLC) स्थापित किये हैं। ये केंद्र निःशुल्क वित्तीय शिक्षा देते हैं, जिसमें ऋण प्रबंधन, बचत और निवेश सलाह शामिल है।
- FLC वित्तीय साक्षरता की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में।

■ वित्तीय साक्षरता सप्ताह:

- RBI प्रत्येक वर्ष प्रमुख वित्तीय अवधारणाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता है।
- इस कार्यक्रम में कार्यशालाएँ, सेमिनार और सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोगों को व्यक्तिगत वित्त के वभिनिन पहलुओं, जैसे बजट, बीमा तथा [डिजिटल बैंकिंग](#) पर शिक्षित करना है।

■ RBI कहता है अभियान:

- यह पहल [डिजिटल बैंकिंग](#), धोखाधड़ी की रोकथाम और शकियत नविवरण जैसे विषयों पर जनता को शिक्षित करती है। मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर, यह अभियान व्यापक दर्शकों तक पहुँच गया है, जिससे वित्तीय प्रणाली में विश्वास बढ़ा है तथा सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को प्रोत्साहित किया गया है।

■ वित्तीय शिक्षा माइक्रोसाइट:

- RBI ने एक समर्पित वित्तीय शिक्षा माइक्रोसाइट लॉन्च की है जो व्यक्तियों को उनकी वित्तीय साक्षरता में सुधार करने में मदद करने के लिये संसाधन, उपकरण और जानकारी प्रदान करती है। यह साइट महिलाओं, बच्चों तथा युवा वयस्कों को लक्षित करते हुए विशेषित अनुभाग प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय शिक्षा विविध समूहों तक पहुँच सके।

■ परियोजना वित्तीय साक्षरता:

- यह परियोजना कार्यशालाओं और अभियानों के माध्यम से स्कूली बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित वभिनिन समूहों को लक्षित करती है। इसका उद्देश्य वित्तीय जागरूकता बढ़ाना तथा ज़िम्मेदार वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा देना है।

■ भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन योजनाएँ

◦ प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY):

- यह प्रमुख योजना बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी को बैंक खाते, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक कफियती पहुँच प्रदान करने के लिये शुरू की गई थी।
- इस पहल से सफलतापूर्वक 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे नकदी लेनदेन पर निर्भरता काफी कम हुई है और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

■ अटल पेंशन योजना (APY):

- [अटल पेंशन योजना](#) एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे वर्ष 2015 में सभी भारतीयों, विशेषकर गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 1000 से 5000 रुपए की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था।
- इसका प्रशासन [राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली \(National Pension System- NPS\)](#) के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधकिरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) द्वारा किया जाता है तथा इसमें 18-40 वर्ष की आयु के नागरिक शामिल होते हैं, एवं इसमें शामिल होने की आयु के आधार पर अंशदान का स्तर अलग-अलग होता है।

- इस योजना के तहत अभिदिता के जीवनसाथी को आजीवन पेंशन प्रदान की जाती है तथा दोनों की मृत्यु होने पर नामति व्यक्तिको संपूर्ण धनराशा प्रदान की जाती है ।
- लोगों को अपनी सेवानिवृत्त के लिये बचत करने हेतु प्रोत्साहति करके, APY वतितीय साक्षरता को भी बढावा देता है, वशिष रूप से नमिन आय वर्ग के बीच, तथा उन्हें अपने वतितीय भवषिय की योजना बनाने में सशक्त बनाता है ।
- **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS):**
 - **NPS** एक **सवैच्छिक सेवानिवृत्त बचत** योजना है जसि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में शुरू कया गया था जो व्यक्तियों को नयिमति योगदान के माध्यम से अपनी सेवानिवृत्त के लिये बचत करने हेतु प्रोत्साहति करती है ।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):**
 - **PMJJBY** एक **जीवन बीमा योजना** है जो कसि भी कारण से मृत्यु होने पर कवरेज प्रदान करती है ।
 - यह योजना **18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिये** उपलब्ध है, जसिका न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए है ।
 - कफायती जीवन बीमा की पेशकश करके, यह उन व्यक्तियों के बीच वतितीय सुरक्षा को बढावा देता है जो अन्यथा ऐसी कवरेज का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते ।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):**
 - PMSBY व्यक्तियों को 20 रुपये प्रत वर्ष के न्यूनतम प्रीमियम पर दो प्रकार की बीमा कवरेज प्रदान करती है ।
 - इसमें दुर्घटनावश मृत्यु, पूर्ण वकिलांगता और आंशिक वकिलांगता को कवर कया जाता है, जसिमें मृत्यु या पूर्ण वकिलांगता के लिये 2 लाख रुपए तक तथा आंशिक वकिलांगता के लिये 1 लाख रुपए तक का कवरेज शामिल है ।
 - यह योजना आम जनता, वशिषकर नमिन आय वर्ग के लोगों के लिये बीमा सुलभ बनाने के लिये तैयार की गई है ।
- **अन्य प्रमुख पहल:**
 - **भारतीय प्रतभित एवं वनिमिय बोर्ड (सेबी):**
 - **सेबी** नै प्रतभित बाज़ार के बारे में नविशकों को शक्ति करने के लिये **सारथी** नामक एक मोबाइल ऐप वकिसति कया है ।
 - यह ऐप **KYC प्रकरयि, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड** और नविशक शकियात नविरण तंत्र जैसे वषियों पर जानकारी प्रदान करता है । यह हिंदी और अंगरेज़ी में उपलब्ध है और इसका उद्देश्य नविशकों को शेयर बाज़ार के बारे में जानकारी प्रदान करना है ।
- **नविशक शक्ति एवं संरक्षण नधि प्राधकिरण (IEPFA):**
 - **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय** के अंतर्गत IEPFA, व्यक्तियों को बचत, नविश और पूंजी नरिमाण के लाभों के बारे में शक्ति करने के लिये **नविशक जागरूकता कार्यक्रम (Investor Awareness Programs - IAP)** आयोजति करता है ।
 - प्राधकिरण लोगों को सूचति नविश नरिणय लेने में सहायता के लिये **शैक्षिक संसाधन भी प्रदान** करता है ।
- **स्कूल पाठ्यक्रम एकीकरण:**
 - जीवन कौशल के रूप में वतितीय साक्षरता के महत्व को स्वीकार करते हुए, **राष्ट्रीय शक्ति नीति (NEP) 2020** स्कूल पाठ्यक्रम में वतितीय शक्ति को एकीकृत करने पर जोर देती है ।
 - **राष्ट्रीय वतितीय शक्ति केंद्र (National Centre for Financial Education- NCFE)** द्वारा मनी **स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम (Money Smart School Program- MSSP)** का उद्देश्य स्कूलों में वतितीय साक्षरता में सुधार हेतु नषिपक्ष वतितीय शक्ति प्रदान करना है, जो छात्रों के समग्र वकिस के लिये एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है ।

भारत में वतितीय साक्षरता का क्या महत्त्व है?

- **वतितीय समावेशन को बढावा देना:**
 - वतितीय साक्षरता नागरिकों और वतितीय सेवाओं के बीच के अंतर को कम करती है तथा लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिये सशक्त बनाती है ।
 - **बैंकिंग, बीमा और पेंशन योजनाओं** को समझने से वविधि पृष्ठभूमि के लोगों को इन आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने और उनसे लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है ।
- **गरीबी और असमानता कम करना:**
 - वतितीय रूप से साक्षर व्यक्त बचत, नविश और उधार के बारे में **सोच-समझकर नरिणय** लेते हैं, जसिसे **आर्थिक सुरक्षा बढ** सकती है और **उच्च लागत वाले उधार पर नरिभरता कम** हो सकती है ।
 - इससे **आय असमानता कम** होती है और आर्थिक रूप से वंचति समूहों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिलती है ।
- **छोटे व्यवसायों को समर्थन:**
 - **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)**, जो भारत के **सकल घरेलू उत्पाद** में 30% का योगदान देते हैं और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, भारत की आर्थिक वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, फरि भी उन्हें अक्सर वतितीय कुप्रबंधन के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ।
 - वतितीय साक्षरता **उद्यमियों को नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने, नविश की योजना बनाने** और ऋण का बुद्धिमानी से उपयोग करने के कौशल से लैस करती है, जसिसे उनकी **प्रतसिपर्द्धात्मकता** और दीर्घायु बढती है ।
- **आर्थिक लचीलापन में सुधार:**
 - वतितीय साक्षरता व्यक्तियों और समुदायों को वतितीय झटकों से बेहतर तरीके से नषिटने में सक्षम बनाती है । जब नागरिक बचत, बीमा और आपातकालीन नधियों के महत्त्व को समझते हैं, तो वे अप्रत्याशति परिस्थितियों के लिये बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं ।
- **जमिंदार उपभोक्ता व्यवहार को प्रोत्साहति करना:**
 - वतितीय अवधारणाओं की ठोस समझ के साथ, नागरिक अपने अधिकारों और जमिंदारियों के प्रतजागरूक हो जाते हैं, जसिसे वतितीय उत्पादों की धोखाधड़ी तथा गलत बकिरी की संभावना कम हो जाती है ।

भारत में वतितीय साक्षरता और समावेशन के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **वित्तीय नरिक्षरता:** भारत में वित्तीय साक्षरता एक महत्त्वपूर्ण कौशल है, लेकिन जनसंख्या का केवल एक छोटा प्रतशित ही वित्तीय रूप से साक्षर है।
- **डजिटल डवाइड:** भारत की ग्रामीण आबादी को स्मार्टफोन की कम पहुँच, इंटरनेट कनेक्टिविटी और खराब सड़क पहुँच और बजिली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण **डजिटल वित्तीय सेवाओं** तक सीमति पहुँच का सामना करना पड़ता है। यह डजिटल डवाइड वंचित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को प्रतर्बिंधित करता है, जिससे आर्थिक सशक्तीकरण प्रभावित होता है।
- **बैंक खातों तक गैर-सार्वभौमिक पहुँच:**
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** के तहत की गई महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद वर्ष 2024 तक भारत में लगभग 22% वयस्क बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहेंगे। इसका मतलब है कि लगभग 19 करोड़ वयस्क अभी भी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच से वंचित हैं।
- **लैंगिक असमानता:** सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ भारत में महिलाओं के वित्तीय समावेशन को सीमति करती हैं **केवल 33% महिलाएँ इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा 57% है**, जो डजिटल पहुँच में कमी को दर्शाता है। इसके अतरिकित सीमति संपत्ता स्वामित्व और महिलाओं के बीच कम वित्तीय साक्षरता दर इस अंतर को बढ़ाती है, जिससे उनके आर्थिक सशक्तीकरण और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न होती है।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और नकदी प्रभुत्व:** भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक रूप से संचालित होता है, जिसमें लगभग **90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों** में लगे हुए हैं।
 - नकद लेन-देन पर नरिभरता और सीमति औपचारिक ऋण पहुँच के कारण इस क्षेत्र में डजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है।
 - RBI के अनुसार, मार्च 2024 तक, **उपभोक्ता वयस में नकदी की हसिसेदारी 60% होगी**, लेकिन **कोविड-19** के बाद डजिटल भुगतान की ओर रुझान के कारण इसकी हसिसेदारी तेज़ी से घट रही है।
- **ऋण की उपलब्धता का अभाव:** नमिन आय वाले व्यक्तियों और अनौपचारिक व्यवसायों को कफियाती ऋण उपलब्ध कराना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
 - औपचारिक ऋण इतहिस और वशि्वसनीय डेटा की कमी के कारण, ऋणदाताओं को ऋण-योग्यता का आकलन करने में कठनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके परणामस्वरूप **उच्च उधार लागत** और कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिये **सीमति ऋण उपलब्धता** होती है।
- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** जैसी योजनाओं ने बैंक खाते खोलने में सफलता हासिल की है, लेकिन इनमें से कई खाते अभी भी नषिकरयि हैं।
 - **सीमति वित्तीय साक्षरता** के कारण सार्थक उपयोग का अभाव, औपचारिक बैंकिंग प्रणालियों में कम वशिवास तथा इन खातों को **बनाए रखने की उच्च लागत ने इनके इच्छति लाभों को** कमजोर कर दिया है।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** डजिटल वित्तीय सेवाओं के तेज़ी से वसितार ने साइबर सुरक्षा जोखिम को बढ़ा दिया है। वर्ष 2022 में साइबर अपराध की रपिोरटिंग में 24.4% की वृद्धि हुई और 2021 (NCRB) में 52,974 की तुलना में 65,893 मामले दर्ज किये गए। डजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि और साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में उपयोगकर्त्ताओं की सीमति जागरूकता वित्तीय समावेशन को सुरक्षित करने के लिये प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

आगे की राह

- **शक्षिा में वित्तीय साक्षरता को शामिल करना:** प्रारंभिक आयु में ही बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं को प्रदान करने के लिये स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को शामिल करने की आवश्यकता है। वित्तीय रूप से जागरूक युवा आबादी का नरिमाण करने हेतु बजट, बचत, नविश और ऋण की समझ जैसे वषियों को शामिल कया जाना चाहयि।
- **लक्षति कार्यशालाएँ और जागरूकता अभयान आयोजति करना:** पहुँच में सुधार के लिये वभिन्न जनसांख्यिकी- ग्रामीण आबादी, शहरी युवा और वरषित नागरिकों को लक्षति करते हुए कार्यशालाएँ और अभयान आयोजति कये जाने चाहयि।
 - वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को समावेशति सुनशिचति करने के लिये प्रत्येक समूह की वशिषिट वित्तीय आवश्यकताओं और समझ के स्तर को धयान में रखना चाहयि।
- **वित्तीय शक्षिा के लिये डजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना:** डजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप बड़े पैमाने पर वित्तीय शक्षिा का प्रसार कर सकते हैं।
 - इंटरैक्टिवि ऐप्स, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सोशल मीडिया अभयान वित्तीय अवधारणाओं को सीखना अधिक रोचक और सुलभ बनाते हैं, वशिष रूप से युवा, तकनीक-प्रेमी पीढ़ी के लिये।
- **वित्तीय समावेशन प्रयासों को बढ़ावा देना:** वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना प्राथमकिता बनी हुई है। **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** और माइक्रोफाइनेंस को बढ़ावा देने जैसी पहल वंचित समुदायों को आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं, साथ ही वित्तीय समावेशन और साक्षरता को भी बढ़ावा देती हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

2010-2011:

प्रश्न: भारत के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिार कीजयि: (2010)

1. बैंकों का राष्ट्रीयकरण
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन
3. बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों को गोद लेना

भारत में "वित्तीय समावेशन" के लिये उपर्युक्त में से कौन-सा/से कदम उठाया/उठाए जाना/जाने चाहिये?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

Q. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिये आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों वित्तीय समावेशन होगा? अपने मत की पुष्टि के लिये तर्क प्रस्तुत कीजिये।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/financial-literacy,-financial-inclusion-and-digital-banking-initiatives>

